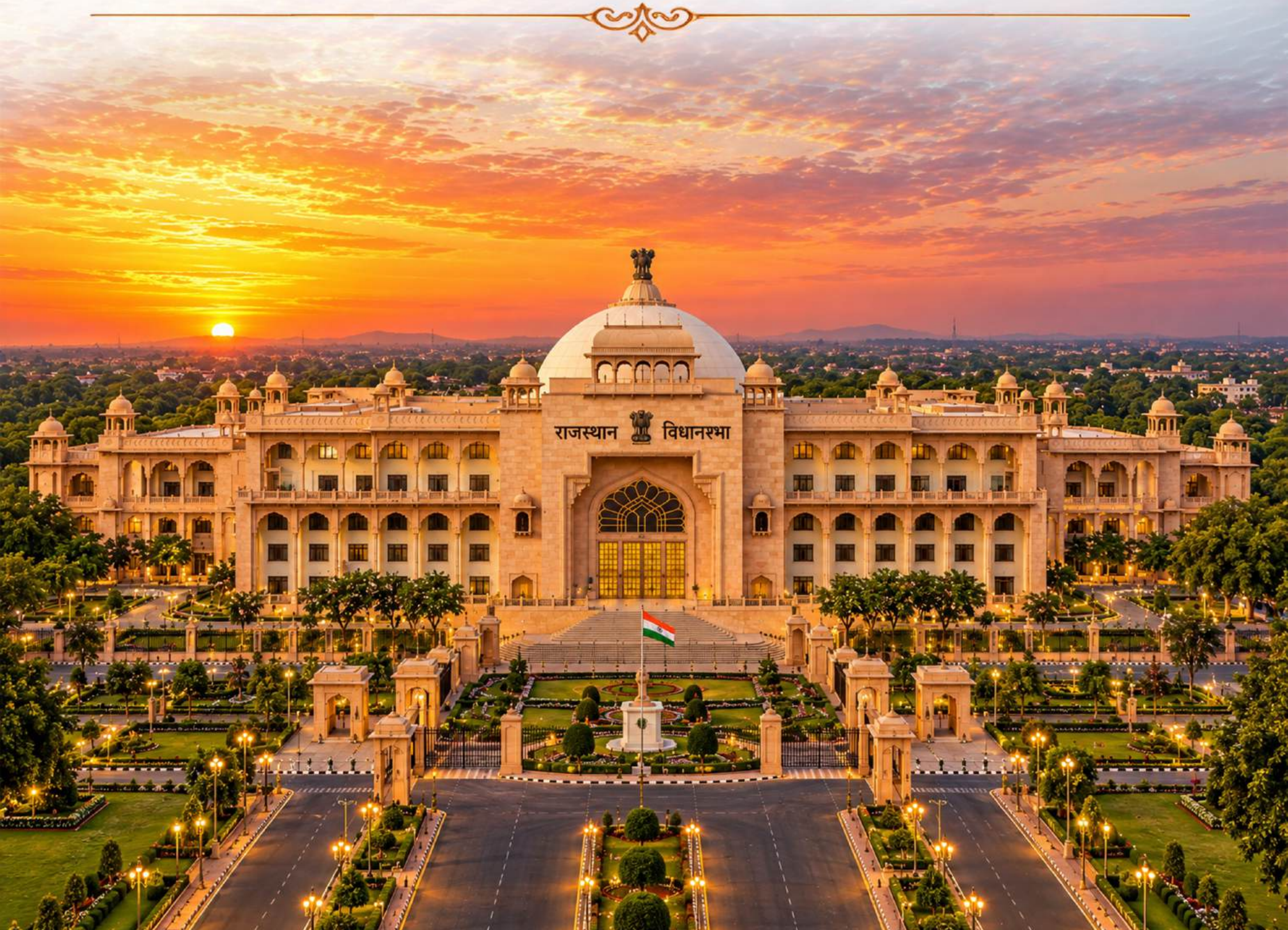


CONNECT CIVILS

For RAS and other RPSC Exams. According to new pattern

राजस्थान राजव्यवस्था प्रश्न बैंक

Cover Complete Rajasthan Polity through 300 + Questions and solutions





अनुक्रमणिका

(1)	राज्यपाल.....	2
(2)	मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्.....	33
(3)	राजस्थान विधानसभा.....	56
(4)	राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायिक निकाय.....	87
(5)	महाधिवक्ता.....	106
(6)	प्रशासनिक व्यवस्था: मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप-खण्ड अधिकारी, तहसीलदार.....	109
(7)	राजस्थान लोक सेवा आयोग.....	130
(8)	राजस्थान निर्वाचन आयोग.....	140
(9)	राजस्थान सूचना आयोग.....	144
(10)	राजस्थान राज्य महिला आयोग.....	150
(11)	लोकायुक्त.....	154
(12)	राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं का प्रशासन.....	160
(13)	राजस्व मंडल.....	182
(14)	राजस्थान मानवाधिकार आयोग - (RAS प्रा.प.से हटा दिया गया है).....	190

Scan this QR code to attempt topicwise PYQs →



प्रश्न बैंक में कोई गलती मिली? बधाई हो, आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है! 😊

QR कोड →

स्कैन करें और हमें इसकी जानकारी दें। आपका इनाम? आपके शिक्षकों और ईश्वर का आशीर्वाद 🙏 - जो आपको इस परीक्षा में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी सफल होने में मदद करेगा!





(1) राज्यपाल

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए:

- (A) अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या मंत्रिपरिषद् के द्वारा करेगा।
- (B) भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के बजाय संघीय मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) द्वारा की जाती है, जिसे राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है।
- (C) अतिरिक्त प्रभार मिलने पर राज्यपाल को संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पुनः शपथ लेनी होती है।
- (D) अनुच्छेद 157 के अनुसार, राज्यपाल पद के लिए केवल तीन संवैधानिक अर्हताएँ अनिवार्य हैं।
- दिये गये कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए :
- (1) केवल (A), (B) व (C)
- (2) केवल (B) व (C)
- (3) केवल (A) व (D)
- (4) केवल (A), (B), (C) व (D)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या:-

(A) X	अनुच्छेद 154(1) - राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कथन में "अधीनस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों" कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 154 में "अधीनस्थ अधिकारियों" का उल्लेख है।
(B) ✓	अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति — राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, बल्कि संघीय मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (वारंट) के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होता है तथा नियुक्ति संबंधी अधिपत्र को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है।

(C) ✓

अनुच्छेद 159 - राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। किसी राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिये जाने पर उन्हें पुनः शपथ लेनी होती है।

(D) X

अनुच्छेद 157 - राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ — कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब-

- वह भारत का नागरिक हो और;
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।

कथन में "केवल तीन संवैधानिक अर्हताएँ" कहा गया है, जबकि अनुच्छेद 157 में दो अर्हताएँ हैं।

अतिरिक्त जानकारी

अनुच्छेद 154 - राज्य की कार्यपालिका शक्ति

- (1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

नोट :

- अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद् से है, जो राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संचालित करते हैं।
- राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो स्वतंत्र और संवैधानिक पद है।

अनुच्छेद 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति

- राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
- ❖ राष्ट्रपति इस संदर्भ में वारंट जारी करता है। नियुक्ति संबंधी वारंट को राज्य का मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- ❖ राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ हैं।
- 1. राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह निवासी है।
- 2. राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है।

**(2) मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद्**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) हरिदेव जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार पद की शपथ ली, किंतु केवल एक बार ही अपना पाँच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सके।
 (B) वर्ष 1988 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को 'दिवराला सती कांड' (1987) के पश्चात उत्पन्न राजनीतिक एवं नैतिक दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
 (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	हरिदेव जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार शपथ ली, लेकिन वे एक बार भी अपना पाँच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा नहीं कर सके।
(B) X	वर्ष 1988 में दिवराला सती कांड के कारण इस्तीफा हरिदेव जोशी को देना पड़ा था, न कि शिवचरण माथुर को।

हरिदेव जोशी

- ❖ वे राजस्थान के एक मात्र ऐसे नेता हैं जो वर्ष 1952 से अपनी मृत्यु तक लगातार 10 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए।
- ❖ हरिदेव जोशी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीन बार शपथ ग्रहण की, लेकिन एक बार भी अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके।
- ❖ अपने प्रथम कार्यकाल (1973-1977) के दौरान उन्होंने जोगिंदर सिंह और वेदपाल त्यागी जैसे राज्यपालों के साथ कार्य किया।
- ❖ इन्होंने वर्ष 1987 में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया, जिसे मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया था।
- ❖ वर्ष 1988 में प्रसिद्ध दिवराला सती कांड के कारण उत्पन्न नैतिक दबाव के चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
- ❖ वे राजस्थान विधानसभा में 'सरकारी मुख्य सचेतक' (1957-1964), नेता प्रतिपक्ष और 'हरिजन सेवक संघ' के अध्यक्ष भी रहे।
- ❖ प्रशासनिक अनुभव के साथ उन्होंने असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएँ दीं।

कार्यकाल	अवधि	शपथ दिलाने वाले राज्यपाल
प्रथम	11.10.1973 से 29.04.1977	जोगिंदर सिंह
द्वितीय	10.03.1985 से 20.01.1988	ओ.पी. मेहरा
तृतीय	04.12.1989 से 04.03.1990	सुखदेव प्रसाद

शिवचरण माथुर

- ❖ इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में दो बार (1981-1985 और 1988-1989) शपथ ग्रहण की।
- ❖ मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय ये भीलवाड़ा की मांडलगढ़ विधानसभा सीट से निर्वाचित होकर आए थे।
- ❖ वर्ष 1985 में डीग के विधायक राजा मानसिंह की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु के बाद उत्पन्न विवाद के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
- ❖ इन्होंने वर्ष 1999 से 2003 के बीच राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

कार्यकाल	अवधि	विशेष घटना
प्रथम	14.07.1981 से 23.02.1985	राजा मानसिंह कांड के कारण इस्तीफा
द्वितीय	20.01.1988 से 04.12.1989	प्रशासनिक सुधारों पर जोर

2. निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (A) भैरोसिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ के समय विधानसभा सदस्य नहीं थे।
 (B) राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के पश्चात, हरिदेव जोशी ने असम, मेघालय और बिहार के 'राज्यपाल' के रूप में कार्य किया।
 (C) जयनारायण व्यास प्रथम विधानसभा चुनाव में दो स्थानों से हारने के पश्चात, किशनगढ़ सीट से कांग्रेस विधायक चांदमल मेहता के त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान पर हुए उपचुनाव में विजयी होकर राज्य के मुख्यमंत्री बने।

नीचे दिये गये कूटों की सहायता से **सही उत्तर** का चयन कीजिए :

**(3) राजस्थान विधानसभा**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की शक्ति केवल संसद के पास है, बशर्ते संबंधित राज्य की विधानसभा ने विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया हो, और ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
- (B) विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 04 महीने तक रोके रख सकती है उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?
- (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
 (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (3)

व्याख्या:-

(A) ✓	अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की शक्ति संसद के पास होती है, बशर्ते संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। संसद द्वारा पारित यह कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता तथा इसे साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।
(B) ✓	विधान सभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है — पहली बार अधिकतम 3 माह तथा दूसरी बार अधिकतम 1 माह तक।

अतिरिक्त जानकारी

अनुच्छेद 169. राज्यों में विधान परिषदों का सृजन अथवा उत्सादन

- ❖ संसद एक विधानपरिषद को (यदि यह पहले से है) विघटित कर सकती है और (यदि पहले से नहीं है) इसका गठन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे।
- ❖ इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है -
 - राज्य विधानसभा द्वारा पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों की

संख्या के दो-तिहाई बहुमत से विधानपरिषद् के सृजन या समाप्ति का प्रस्ताव पारित कर दे।

- ❖ तत्पश्चात् संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्त कर सकती है।
- ❖ संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा और सामान्य विधान की तरह (अर्थात् साधारण बहुमत से) पारित किया जायेगा।

विधान परिषद् के अधिकार तथा शक्तियाँ :

- ❖ विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 04 महीने तक रोके रख सकती है। पहली बार में तीन माह के लिए और दूसरी बार में एक माह के लिए।
- ❖ विधान सभा द्वारा पुनः विधेयक को पारित करने पर वह विधान परिषद के पास दूसरी बार आने पर भी यदि परिषद उसे पास नहीं करती है उसे संशोधनों सहित लौटा देती है या उसे एक माह तक रोके रखती है (किसी भी स्थिति में) वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मानकर राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है।
- ❖ विधान परिषद को धन विधेयक को केवल मात्र 14 दिन विलम्बित करने का अधिकार व शक्ति प्राप्त है। यदि विधान परिषद 14 दिन से अधिक धन विधेयक को अपने पास रोके रखती है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है।

2. राजस्थान विधानसभा समितियां (2025-26) से संबंधित सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I		सूची-II	
(समिति)		(सभापति)	
(A)	याचिका एवं सदाचार समिति	i.	बाबू सिंह राठौड़
(B)	राजकीय उपक्रम समिति	ii.	कैलाश चन्द वर्मा
(C)	प्राक्कलन समिति 'ख'	iii.	संदीप शर्मा
(D)	प्रश्न एवं संदर्भ समिति	iv.	कालीचरण सराफ

सही उत्तर का चयन कीजिए :

**(4) राजस्थान उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायिक निकाय**

1. निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था ?

- (1) 21 जून 1949
- (2) 25 अगस्त 1949
- (3) 29 अगस्त 1949
- (4) 26 जनवरी 1950
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (3)

व्याख्या:-

- ❖ राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में किया गया था। इसकी स्थापना हेतु अधिसूचना 25 अगस्त 1949 को जारी की गई थी तथा उसी के अनुसार 29 अगस्त 1949 को उद्घाटन की तिथि निर्धारित की गई। इस अवसर पर राजप्रमुख सवाई मानसिंह की अध्यक्षता में उद्घाटन हुआ तथा न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा सहित अन्य न्यायाधीशों ने शपथ ग्रहण की थी।

अतिरिक्त जानकारी

राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापना -

- ❖ राजप्रमुख ने 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी कर 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन करने की तिथि निश्चित की।
- ❖ प्रारंभिक बैठक स्थान
 - जयपुर (कोटा क्षेत्राधिकार सहित)
 - उदयपुर
- ❖ उद्घाटन 29 अगस्त, 1949 को राजप्रमुख महामहिम महाराजा सवाई मानसिंह की अध्यक्षता में जोधपुर में किया गया तथा माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा (इलाहाबाद एवं उदयपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ने अन्य 11 न्यायाधीशों के साथ शपथ ली।

2. राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

- (A) न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, जो बाद में भारत के 10वें मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) भी बने।
- (B) न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में 'सबसे कम' कार्यकाल तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे।
- (C) न्यायमूर्ति दीपक वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो बाद में भारत के 27वें मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) बने और उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएँ दीं।

उपर्युक्त में से **असत्य** कथन/नों की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें।

- (1) केवल (C)
- (2) केवल (A) तथा (B)
- (3) केवल (B) तथा (C)
- (4) ना ही (A) , ना ही (B) , ना ही (C)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर:- (1)

व्याख्या:-

(A) ✓	न्यायमूर्ति कैलाश नाथ वांचू राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में सर्वाधिक कार्यकाल (1951 से 1958) तक मुख्य न्यायाधीश रहे। वे संविधान लागू होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने तथा बाद में भारत के 10वें मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) के पद पर भी आसीन हुए। इसलिए यह कथन सही है।
(B) ✓	न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल (केवल 41 दिन) तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इसलिए यह कथन सही है।
(C) X	यह कथन गलत है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं बाद में भारत के 27वें मुख्य न्यायमूर्ति (CJI) बनने वाले व्यक्ति न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा थे, न कि न्यायमूर्ति दीपक वर्मा। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएँ दीं।

3. सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए-

सूची-I		सूची-II	
(अनुच्छेद)		(प्रावधान)	
(A)	223	i.	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
(B)	224	ii.	न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते आदि
(C)	222	iii.	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
(D)	221	iv.	एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण

**(5) महाधिवक्ता**

1. राजस्थान के महाधिवक्ता से संबंधित **सही क्रम** का चयन कीजिए:-

- (A) महेंद्र सिंह सिंघवी
(B) जी. एस. बाफना
(C) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(D) एन. एम. लोढ़ा

सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) (B), (A), (C), (D)
(2) (A), (C), (B), (D)
(3) (A), (B), (D), (C)
(4) (B), (D), (A), (C)
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या :-

♦ **सही क्रम** - (B) जी. एस. बाफना → (D) एन. एम. लोढ़ा
→ (A) महेंद्र सिंह सिंघवी → (C) राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता।

राजस्थान के महाधिवक्ता (क्रमानुसार)		
क्र.सं.	महाधिवक्ता का नाम	महत्वपूर्ण तथ्य
1	जी. सी. कासलीवाल	- प्रथम महाधिवक्ता - सबसे लंबा कार्यकाल
2	डॉ. लक्ष्मी मल सिंघवी	पद्मभूषण से सम्मानित
3	डॉ. एस. के. तिवारी	
6	ए. के. माथुर	कार्यवाहक महाधिवक्ता (मार्च 1982 में)
16	जी. एस. बाफना	
17	एन. एम. लोढ़ा	
18	महेंद्र सिंह सिंघवी	
19	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	- वर्तमान - पदभार ग्रहण - 3 फरवरी 2024

2. राजस्थान के महाधिवक्ता से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (A) संविधान के अनुच्छेद 165(1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, जो 'उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश' नियुक्त होने के लिए अर्हित हो।

(B) संविधान के अनुच्छेद 165(4) के अनुसार, महाधिवक्ता को ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त होगा जिसे विधानसभा समय-समय पर अवधारित करें।

(C) संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, साथ ही उसके पास 05 वर्ष का न्यायिक अनुभव या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहने की योग्यता होनी चाहिए

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A) सही है।
(2) केवल (B) व (C) सही है।
(3) (A), (B) व (C) सही है।
(4) उपर्युक्त में कोई कथन सत्य नहीं है।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	संविधान के अनुच्छेद 165(1) में महाधिवक्ता के लिए वह व्यक्ति अर्हित होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, न कि 'मुख्य न्यायाधीश'।
(B) X	अनुच्छेद 165(4) के अनुसार महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि विधानसभा द्वारा।
(C) X	अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता बनने हेतु भारत का नागरिक होना तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होना आवश्यक है, अर्थात् कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो।, जबकि कथन में 05 वर्ष लिखा गया है।

अतिरिक्त जानकारी

अनुच्छेद 165(3) - कार्यकाल

- महाधिवक्ता का निश्चित कार्यकाल नहीं होता।
- वह राज्यपाल के प्रसादपर्यंत (Pleasure of Governor) पद पर बना रहता है।
- राज्यपाल उसे किसी भी समय पद से हटा सकता है।
- वह राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भी दे सकता है।



(6) प्रशासनिक व्यवस्था: मुख्य सचिव, राज्य सचिवालय, विभिन्न विभागों के निदेशालय, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप-खण्ड अधिकारी, तहसीलदार

1. राजस्थान के मुख्य सचिवों से संबंधित निम्नलिखित में से कौनसा कथन **ग़लत** है?

- (1) भगतसिंह मेहता मुख्य सचिव के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल वाले अधिकारी रहे।
- (2) के.पी.यू. मेनन मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए राज्य के प्रथम उप-लोकायुक्त भी बने।
- (3) मीठालाल मेहता को मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठता क्रम तोड़कर नियुक्त किया गया।
- (4) निरंजन आर्य मुख्य सचिव रहने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी कार्यरत रहे।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या :-

(1) ✓	भगतसिंह मेहता राजस्थान कैडर के प्रथम IAS अधिकारी थे तथा उन्होंने 1958-1964 और 1965-1966 के दौरान सर्वाधिक कार्यकाल तक सेवा दी।
(2) ✓	के.पी.यू. मेनन 1966 से 1968 तक मुख्य सचिव रहे और बाद में राज्य के प्रथम उप-लोकायुक्त भी बने।
(3) ✓	मीठालाल मेहता को 1994 से 1997 के बीच वरिष्ठता क्रम तोड़कर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था।
(4) ✗	निरंजन आर्य 2020 से 2022 तक मुख्य सचिव रहे, लेकिन वे कभी भी मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नहीं रहे।

अतिरिक्त जानकारी

- ❖ टी. श्रीनिवासन 2009 से 2010 तक व डी.बी. गुप्ता 2018 से 2020 तक मुख्य सचिव रहे और बाद में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी कार्य किया।

2. राजस्थान शासन सचिवालय में प्रशासनिक नेतृत्व के सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए:

- (A) उपसचिव
- (B) सचिव
- (C) विशिष्ट सचिव
- (D) सहायक सचिव

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :-

- (1) (A), (B), (C), (D)
- (2) (B), (C), (A), (D)
- (3) (A), (B), (D), (C)
- (4) (B), (A), (C), (D)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या :-

राजस्थान शासन सचिवालय में प्रशासनिक नेतृत्व:

मुख्य सचिव
|
अतिरिक्त मुख्य सचिव
|
प्रमुख शासन सचिव
|
सचिव
|
विशिष्ट सचिव
|
उपसचिव
|
सहायक सचिव
|
अनुभाग अधिकारी
|
सहायक अनुभाग अधिकारी
|
वरिष्ठ लिपिक
|
कनिष्ठ लिपिक
|
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

प्रशासनिक पदानुक्रम (Top to Bottom)

1. **मुख्य सचिव** : राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार।
2. **अतिरिक्त मुख्य सचिव** : महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख (2004 से प्रभावी)।
3. **प्रमुख शासन सचिव** : विभाग के कार्यकारी प्रमुख।
4. **शासन सचिव**: नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन के उत्तरदायी।

**(7) राजस्थान लोक सेवा आयोग**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय एक अध्यक्ष तथा तीन सदस्यों का प्रावधान था।
 (B) 18 जुलाई 2025 से राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्यों का प्रावधान है।
 उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?
 (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
 (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान था, न कि 3 सदस्यों का।
(B) X	18 जुलाई 2025 से आयोग में 10 सदस्य और 1 अध्यक्ष, अर्थात् कुल 11 पदों का प्रावधान है; इसलिए "अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य" वाला कथन गलत है।

RPSC की संरचना**प्रारंभिक संरचना-**

- ❖ स्थापना के समय आयोग में:
 - 1 अध्यक्ष
 - 2 सदस्य
- ❖ प्रथम अध्यक्ष - एस. के. घोष (तत्कालीन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)
- ❖ प्रथम सदस्य
 - 1. देवीशंकर तिवारी 2. एन. आर. चंदोरकर
- ❖ बाद में एस. सी. त्रिपाठी (पूर्व सदस्य, UPSC) को अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सदस्यों की संख्या में परिवर्तन

वर्ष	सदस्य संख्या
स्थापना	2 सदस्य + 1 अध्यक्ष
1962	3 + 1
1965	4 + 1
1985	5 + 1
2011	7 + 1
18 जुलाई 2025	10 + 1 (कुल 11)

2. राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर **सत्य** कथनों का चयन कीजिए:

- (A) सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का मुख्यालय 1958 को जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया।
 (B) राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा शर्त) विनियम 1974 तत्कालीन राज्यपाल सरदार जोगिन्द्र सिंह के कार्यकाल में बनाए गए थे।
 (C) वर्तमान में वर्तमान में श्री लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
 (D) अनुच्छेद 323 के अनुसार, आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जो इसे राज्य विधानमंडल के सामने रखवाएगी।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (B) व (C)
 (2) केवल (A), (B) व (D)
 (3) केवल (C) व (D)
 (4) उपर्युक्त सभी
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (1)

व्याख्या:-

(A) ✓	राज्य पुनर्गठन के बाद 1957 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया। 21 अगस्त 1958 को मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया और 21 अक्टूबर 2000 से कार्यालय घूघरा घाटी, अजमेर में संचालित हो रहा है।
(B) ✓	राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तों) विनियम, 1974 तत्कालीन राज्यपाल सरदार जोगिन्द्र सिंह के कार्यकाल में बनाए गए थे। संविधान का अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से संबंधित विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।
(C) ✓	वर्तमान में वर्तमान में श्री लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ 20 जून 2026 से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
(D) X	अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, न कि राज्य सरकार को।

**(8) राजस्थान निर्वाचन आयोग**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राजस्थान निर्वाचन आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत 24 जुलाई 1995 को स्थापित किया गया।
- (B) राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना के समय मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत और राज्यपाल बलिराम भगत थे।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
 (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या:-

(A) X	राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना 24 जुलाई 1995 को नहीं, बल्कि 1 जुलाई 1994 को अनुच्छेद 243K और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत हुई थी।
(B) ✓	स्थापना के समय मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत थे और राज्यपाल बलिराम भगत थे, जिन्होंने 17 जून 1994 को इसके संबंध में आदेश जारी किए थे।

2. राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर **सत्य** कथनों का चयन कीजिए:

- (A) राज्य निर्वाचन आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं।
- (B) भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता यह है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी हों, और उन्हें कम से कम 5 वर्ष का शासन सचिव पद का अनुभव होना चाहिए।
- (C) राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राज्यपाल या उनके नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं।
- (D) राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है और नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (B) व (C)
 (2) केवल (A), (B) व (D)
 (3) केवल (C) व (D)
 (4) इनमें से कोई नहीं
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राज्य निर्वाचन आयोग एक एकल सदस्यीय संवैधानिक निकाय होता है, जिसमें केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य होने का कोई प्रावधान नहीं है।
(B) X	संविधान में राज्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता संबंधी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है; इसकी योग्यता राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है तथा सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा के कार्यरत या सेवानिवृत्त ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाता है जिसे शासन सचिव पद का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो, और यदि वह सेवा में कार्यरत हो तो नियुक्ति की तिथि से उसे शासन सचिव पद से सेवानिवृत्त माना जाता है।
(C) X	राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। शपथ भी राज्यपाल या उनके नामित व्यक्ति के समक्ष ली जाती है।
(D) X	राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है, न कि राज्य विधानमंडल द्वारा। साथ ही नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

3. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **ग़लत** है?

- (1) नेकरम भसीन न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे।
- (2) इंद्रजीत खन्ना पूर्व मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे।
- (3) राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान 2.50 लाख रुपये है।
- (4) राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (3)

व्याख्या :-



(9) राजस्थान सूचना आयोग

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2008 को किया गया है।
 (B) राजस्थान राज्य सूचना आयोग में 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 3 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
 (2) केवल (B) सही है।
 (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
 (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2008 को नहीं किया गया। वास्तविक रूप से इसका गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग 18 अप्रैल 2006 से क्रियाशील हुआ, जब प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई।
(B) X	राज्य सूचना आयोग में 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, न कि केवल 3। आयोग की संरचना RTI Act, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होती है।

2. राजस्थान राज्य सूचना आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए:

- (A) आयोग अपने क्रियान्वयन संबंधी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य सरकार राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाती है।
 (B) RTI 2019 संशोधन अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
 (C) राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी ने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया, जबकि श्री डी.बी. गुप्ता का कार्यकाल सबसे कम रहा।
 (D) राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय 2013 से राजस्थान सचिवालय जयपुर में स्थित है।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A) व (C)
 (2) केवल (B) व (D)
 (3) केवल (C)
 (4) इनमें से कोई नहीं
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (3)

व्याख्या:-

(A) X	RTI Act, Section 25 के अनुसार राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है, और राज्य सरकार उसे राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाती है। लेकिन प्रश्न में "आयोग अपने क्रियान्वयन संबंधी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और इसे राज्यपाल को प्रस्तुत करता है" लिखा है, जो सही प्रक्रिया नहीं है क्योंकि रिपोर्ट राज्यपाल को सीधे प्रस्तुत नहीं की जाती, बल्कि राज्य सरकार को भेजी जाती है।
(B) X	RTI एक्ट की धारा 16(5) एवं RTI 2019 संशोधन अधिनियम के अनुसार, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के वेतन-भत्तों का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं, इसलिए यह कथन गलत है। कार्यकाल के दौरान इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
(C) ✓	राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्तों में श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल सबसे लंबा और श्री डी.बी. गुप्ता का कार्यकाल सबसे कम रहा।
(D) X	आयोग का मुख्यालय जयपुर में स्थित है और यह 19 अप्रैल 2013 से एच.सी.एम. रीपा परिसर में संचालित हो रहा है, न कि सचिवालय में।

3. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त का वर्तमान कार्यकाल क्या है?

- (1) 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो
 (2) 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो
 (3) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो
 (4) 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

**(10) राजस्थान राज्य महिला आयोग**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
(B) राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा किसी भी समय पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
(2) केवल (B) सही है।
(3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
(4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राजस्थान राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं बल्कि 3 वर्ष निर्धारित है (धारा 4 के अनुसार), इसलिए यह कथन गलत है।
(B) X	आयोग के अध्यक्ष या सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं ना कि राज्यपाल को।

2. राजस्थान राज्य महिला आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?

- (1) श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त होने के बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है।
(2) राजस्थान राज्य महिला आयोग बैठक के लिए अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
(3) आयोग की बैठक में मत बराबर होने की स्थिति में बुलाए गए किसी विषय विशेषज्ञ को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(4) आयोग में किसी पद की रिक्ति के दौरान लिए गए निर्णय अविधिमान्य नहीं माने जाएंगे।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (3)

व्याख्या :-

(1) ✓	श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती 11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025 तक आयोग की अध्यक्ष रहीं। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद से आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है।
(2) ✓	राजस्थान राज्य महिला आयोग की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित न्यूनतम 3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है (धारा 5)।

(3) X	आयोग की बैठक में मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य का होता है, न कि किसी बुलाए गए विषय विशेषज्ञ का। विषय विशेषज्ञ को केवल सलाह देने का अधिकार होता है, मतदान का नहीं।
(4) ✓	आयोग में किसी पद की रिक्ति होने के बावजूद लिए गए निर्णय अवैध नहीं माने जाते (धारा 7)।

3. राजस्थान राज्य महिला आयोग से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए-

- (A) अधिनियम की धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं से संबंधित प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।
(B) आयोग की साधारण बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है।
(C) राज्य में महिला नीति 8 मार्च, 2000 को जारी की गई।
(D) आयोग के सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति/जनजाति या एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला का होना अनिवार्य है।

उपर्युक्त में से **कितने कथन सत्य** है/हैं ?

- (1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या :-

(A) ✓	धारा 16 के अनुसार राज्य सरकार महिलाओं से संबंधित प्रमुख नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करती है, इसलिए यह कथन सही है।
(B) X	आयोग की साधारण बैठक सामान्यतः प्रत्येक 2 माह में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है, न कि हर माह, इसलिए यह कथन गलत है।
(C) ✓	राजस्थान राज्य महिला नीति 8 मार्च, 2000 को जारी की गई थी, इसलिए यह कथन सही है।
(D) X	आयोग की संरचना में एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है। कथन में इसे "SC/ST या OBC महिला" के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह अधिनियम के प्रावधान को सही रूप में व्यक्त नहीं करता।



(11) लोकायुक्त

1. राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अनुसार, लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय राज्यपाल निम्नलिखित में से किनके साथ परामर्श करता है?

- (A) राज्य का गृह मंत्री
 - (B) विधानसभा अध्यक्ष
 - (C) विधानसभा में विपक्ष का नेता
 - (D) मुख्यमंत्री
 - (E) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
 - (F) मुख्यमंत्री द्वारा एक मनोनीत कैबिनेट मंत्री
- नीचे दिये गये कूटों की सहायता से **सही उत्तर** का चयन कीजिए:

- (1) केवल (A), (C) व (D)
- (2) केवल (C) व (E)
- (3) केवल (A), (B) व (F)
- (4) केवल (C), (D) व (E)
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या:-

❖ राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अनुसार **लोकायुक्त की नियुक्ति** राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से परामर्श के बाद की जाती है :-

- 1. विपक्ष दल का नेता
- 2. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश

अतिरिक्त जानकारी

नियुक्ति (धारा 3):

- ❖ राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और सरकारी मुहर वाले एक आधिकारिक नियुक्ति पत्र (वारंट) के जरिए लोकायुक्त और एक या एक से अधिक उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति करेगा।
- ❖ **योग्यता:**
 - उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
 - कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो।
 - किसी राजनैतिक दल के साथ जुड़ाव न हो। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो।
- ❖ **उप-लोकायुक्त की नियुक्ति:** राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त के परामर्श से। (प्रथम उप-लोकायुक्त पूर्व सतर्कता आयुक्त होना अनिवार्य था)।

2. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) लोकायुक्त केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है।
- (B) लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त के विरुद्ध आरोपों की जांच राज्यपाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से करवाई जाती है, और दोषी पाए जाने पर उन्हें राज्यपाल द्वारा पद से हटा दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
- (2) केवल (B) सही है।
- (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
- (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	लोकायुक्त केवल उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही नहीं होता, बल्कि वह उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है। इसलिए योग्यता संबंधी यह कथन असत्य है।
(B) X	राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 6 के अनुसार लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त के विरुद्ध आरोपों की जांच राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी करवा सकते हैं। यदि जाँच में दोष सिद्ध हो जाता है, तो राज्यपाल उस पदाधिकारी को पद से हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि विधानमंडल के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से हटाने का संकल्प पारित हो जाता है, तो राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जाना अनिवार्य हो जाता है।

3. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राज्य लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल इसे विधानसभा में प्रस्तुत करवा देते हैं।
 - (B) श्री के.पी.यू मेनन राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे।
- उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
- (2) केवल (B) सही है।
- (3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
- (4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (1)

**(12) राजस्थान में पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं का प्रशासन**

1. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) राजस्थान में नगर निकायों में महापौर अपना त्यागपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी को और सभापति अपना त्यागपत्र जिला कलेक्टर को सौंपते हैं।
(B) नगर निगम में सदस्य और अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
(2) केवल (B) सही है।
(3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
(4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राजस्थान के नगर निकायों में नगर निगम के महापौर अपना त्यागपत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देते हैं, लेकिन नगर परिषद के सभापति अपना त्यागपत्र जिला कलेक्टर को नहीं बल्कि आयुक्त को सौंपते हैं।
(B) X	नगर निगम में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि महापौर (अध्यक्ष) का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यही व्यवस्था नगरपालिका और नगर परिषद में भी लागू होती है।

अतिरिक्त जानकारी

राजस्थान के नगर निकायों में त्यागपत्र देने का अधिकारी:

- ❖ नगरपालिका: अध्यक्ष → अधिशाषी अधिकारी, पार्षद एवं उपाध्यक्ष → अध्यक्ष
- ❖ नगर परिषद: सभापति → आयुक्त, पार्षद एवं उपसभापति → सभापति
- ❖ नगर निगम: महापौर → मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पार्षद एवं उपमहापौर → महापौर

राजस्थान के नगर निकायों में अध्यक्ष / सदस्य का चुनाव

- ❖ नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से और अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

2. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए:

- (A) ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 प्रत्येक पंचायत में ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।
(B) राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय अधिसूचित और कार्यरत हैं।

उपरोक्त में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं ?

- (1) केवल (A) सही है।
(2) केवल (B) सही है।
(3) (A) एवं (B) दोनों सही हैं।
(4) न तो (A) न ही (B) सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या:-

(A) X	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 प्रत्येक पंचायत में ग्राम न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता। अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी प्रावधान नहीं है।
(B) ✓	राजस्थान में 45 ग्राम न्यायालय अधिसूचित एवं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, देश के 15 राज्यों में 481 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं तथा 10 राज्यों में 309 ग्राम न्यायालय सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

3. राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्तावों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-कौन से कथन सही हैं?

- (A) अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।
(B) 2/3 बहुमत से पारित होने पर संबंधित पद रिक्त हो जाता है।
(C) सरकार गठन के पहले एक वर्ष तथा अंतिम एक वर्ष के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

नीचे दिये गये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) केवल (A), (B) व (C)
(2) केवल (A), (B) व (D)
(3) केवल (C) व (D)
(4) इनमें से कोई नहीं
(5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (4)

व्याख्या:-

(A) X	राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुल सदस्य संख्या के 1/4 नहीं, बल्कि 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है।
(B) X	अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से नहीं, बल्कि कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होने पर संबंधित पद रिक्त माना जाता है।



(13) राजस्व मंडल

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
 (A) राजस्व मंडल एक अर्ध-न्यायिक संस्था है।
 (B) राजस्थान का राजस्व मंडल जयपुर में स्थित है।
 (C) राजस्व मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिलाधीश का होता है।
 उपर्युक्त में से **असत्य** कथन/नों की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें।
 (1) केवल (C)
 (2) केवल (A) तथा (B)
 (3) केवल (B) तथा (C)
 (4) ना ही (A), ना ही (B), ना ही (C)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर:- (3)

व्याख्या:-

(A) ✓	राजस्थान का राजस्व मंडल एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जो राजस्व संबंधी मामलों में अंतिम अपील और पुनर्विलोकन (revision) की सुनवाई करता है।
(B) ✗	राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय जयपुर में नहीं, बल्कि अजमेर में स्थित है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 6 में इसका प्रावधान है।
(C) ✗	यह कथन गलत है क्योंकि राजस्व मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिलाधीश का नहीं बल्कि सहायक जिलाधीश (Assistant Collector / Sub - Divisional Officer) का होता है।

2. निम्नलिखित में से कौनसा कथन **गलत** है?
 (1) राजस्थान राजस्व बोर्ड में एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं।
 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम राजस्थान राज्य में भूमि से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
 (3) राजस्थान में भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 में लागू किया गया।
 (4) राजस्व मंडल की स्थापना से संबंधित अध्यादेश 26 नवंबर 1949 से लागू हुआ।
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर:- (4)

व्याख्या :-

(1) ✓	राजस्थान राजस्व बोर्ड में एक अध्यक्ष और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, इसलिए यह कथन सही है। बोर्ड अपील, पुनरीक्षण और संदर्भ के मामलों का निपटारा करता है।
-------	---

- (2) ✓ राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम राजस्थान राज्य में भूमि से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
 (3) ✓ राजस्थान में भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 में लागू किया गया था (जिसमें बाद में 1959 में संशोधन हुआ), इसलिए यह कथन सही है। अधिनियम का उद्देश्य बड़े ज़मींदारों से अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित कर उसे छोटे किसानों और किरायेदारों को वितरित करना था।
 (4) ✗ राजस्व मंडल की स्थापना से संबंधित अध्यादेश 26 नवंबर 1949 को नहीं बल्कि 7 अप्रैल 1949 को जारी हुआ था और यह 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ।

अतिरिक्त जानकारी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15)

- ❖ यह एक व्यापक अधिनियम है, जो राजस्थान राज्य में भूमि से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
- ❖ अधिनियम में राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और ग्राम सेवकों की नियुक्ति, उनके कर्तव्य और शक्तियों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।
- ❖ इसके अतिरिक्त, अधिनियम में भूमि अभिलेख और मानचित्रों की तैयारी एवं रखरखाव, राजस्व और किराया निर्धारण, संपत्तियों का विभाजन, और राजस्व संग्रह की प्रक्रिया को भी निर्धारित किया गया है।

3. राजस्थान राजस्व मंडल के अधीनस्थ निम्नलिखित न्यायालय के **सही क्रम** का चयन कीजिए:-

- (A) उपखण्ड अधिकारी
 (B) राजस्व अपील प्राधिकारी
 (C) सहायक कलक्टर
 (D) भू-प्रबन्ध पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
 सही उत्तर का चयन कीजिए :
 (1) (B), (A), (C), (D)
 (2) (A), (C), (B), (D)
 (3) (A), (B), (D), (C)
 (4) (B), (D), (A), (C)
 (5) अनुत्तरित प्रश्न

**(14) राजस्थान मानवाधिकार आयोग - (RAS प्रा.प.से हटा दिया गया है)**

1. राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है और यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है?

- (1) राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार की सिफारिश पर
- (2) राष्ट्रपति द्वारा, उसी प्रक्रिया से जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लागू होती है
- (3) राज्यपाल द्वारा, उसी प्रक्रिया से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है
- (4) राष्ट्रपति द्वारा, उसी प्रक्रिया से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है।
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (2)

व्याख्या :-

- (B) ✓ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यह प्रावधान **राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 23** के अनुसार है। हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समान होती है, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए, या कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद को धारण करे, तो भी उसे हटाया जा सकता है। इसलिए यह कथन सही है।

2. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए-

- (A) आयोग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में न्यायाधिपति श्री एन.के. जैन का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है।
- (B) आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में न्यायाधिपति श्री एच.आर. कुडी का कार्यकाल सर्वाधिक लंबा रहा है।
- (C) आयोग के सभी सदस्य एवं अधिकारी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 के अंतर्गत 'लोक सेवक' माने जाते हैं।
- (D) राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता यह निर्धारित की गई है कि आयोग के सभी सदस्य उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश हों या ऐसे जिला न्यायाधीश हों, जिनके पास कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं/हैं ?

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4
- (5) अनुत्तरित प्रश्न

उत्तर- (1)

व्याख्या :-

(A) ✓	न्यायाधिपति श्री एन.के. जैन का कार्यकाल स्थायी अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक लंबा रहा है (2005-2010)।
(B) ✓	न्यायाधिपति श्री एच.आर. कुडी का कार्यकाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक लंबा रहा है (2012-2016)।
(C) ✓	आयोग के सभी सदस्य एवं अधिकारी IPC की धारा 21 के अंतर्गत 'लोक सेवक' माने जाते हैं।
(D) X	यह कथन गलत है क्योंकि इसमें केवल उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश की बात की गई है, जबकि वास्तविक प्रावधान के अनुसार अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं तथा सदस्य की योग्यता अलग-अलग निर्धारित है—जिसमें मानवाधिकार विशेषज्ञ तथा उच्च न्यायालय/जिला न्यायाधीश (कम से कम 7 वर्ष अनुभव) शामिल हैं। इसलिए "केवल मुख्य न्यायाधीश" वाली शर्त गलत है।

अतिरिक्त जानकारी

राज्य मानवाधिकार आयोग - संरचना और योग्यता

- ❖ संरचना (संशोधित 2006 अधिनियम): आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे (वर्तमान में यही प्रावधान लागू है)।
- ❖ अध्यक्ष (2019 संशोधन के बाद): उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त अन्य न्यायाधीश।
- ❖ (पहले केवल मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान था)
- ❖ **सदस्य 1:** उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (वर्तमान या पूर्व) या जिला न्यायाधीश, जिनके पास कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो।
- नोट :** कार्यरत/पूर्व न्यायाधीश या जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है।
- ❖ **सदस्य 2:** मानवाधिकारों के मामलों का विशेषज्ञ या जानकार।
- ❖ **नोट :-** दोनों सदस्यों की योग्यता अलग - अलग है।